प्रभाग, जम्मू व कश्मीर मामला विभाग और प्रधान मंत्री कार्यलय में विशेष प्रकोष्ठ द्वारा मानीटर किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज

(i) प्रधान मंत्री ने 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, 1996 तक उत्तर पूर्व के सभी सात राज्यों का दौरा किया। दौरों के समापन पर, प्रधान मंत्री ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कतिपय नए पैकेजों की घोषणा की। नए पैकेजों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

1. सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करेंगे।

2. चालू परियोजनाओं के लिए पूरी वित्त व्यवस्था।

3. ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को केन्द्र से शत प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

4. रोजगार आश्वासन स्कीम को उत्तर-पूर्वी राज्यों में सभी ब्लाकों तक बढ़ाया जाएगा।

5. उत्तर-पूर्वी राज्यों को उन्नत ऋण प्रवाह।

6. दूर-संचार तथा इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिए उत्तर-पूर्व का पूर्ण कवरेज।

7. उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति विकसित की जाएगी।

8. एक एकीकृत पर्यटन विकास योजना तैयार की जाएगी।

9. 6100 करोड़ रु० की कुल अनुमानित लागत पर प्रत्येक राज्य के लिए परियोजना पैकेज घोषित किया गया।

(ii) प्रधान मंत्री ने 13-14 फरवरी 1997 को जम्मू व कश्मीर यात्रा के दौरान विकास प्रक्रिया को तेज करने और जम्मू व कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने की दृष्टि से निम्नांकित पैकेजों की घोषणा की।

— राज्य वार्षिक योजना (1996-97) का परिव्यय 1250 करोड़ रु० तक बढ़ाया।

— नौवीं पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त परिव्यय व्यवस्था हेतु राज्य सरकार को सक्षम बनाया जाएगा।

— वार्षिक योजना 1997-98 को आगे बढ़ाया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ आवश्यक समर्थन दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित योजना परिव्यय अनुमानित है और संसाधनों में गैर-योजना अन्तराल को पाटने के लिए निधियां भी उपलब्ध कराई जाती है।

— केन्द्र सरकार उग्रवाद के कारण क्षतिग्रस्त आधार संरचना के पुनर्स्थापन हेतु अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराएगी। नौवीं योजना में ग्रामीण विकास तथा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रयोजनार्थ लगभग 1500 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकारों को क्षतिग्रस्त अवसंरचना की बहाली लागत को इस राशि के नाम डालने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

— राज्य के और अधिक कस्बों को प्रधान मंत्री के एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा।

— केन्द्रीय परियोजना से विद्युत आवंटन को 600 मेगावाट से 876 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा ताकि राज्य में विद्युत की कमी को पूरा किया जा सके।

— डल तथा अन्य महत्वपूर्ण झीलों के संरक्षण तथा विकास, घाटी में बाढ़ नियंत्रण हेतु मास्टर प्लान और गंगा कार्य योजना की तरह झेलम के नौवहन तथा पर्यावरणीय पहलुओं में सुधार हेतु कार्य योजना जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विदेशी सहायता सहित विशेष वित्त पोषण कार्यविधि विकसित की जाएगी।

— जम्मू व कश्मीर में उर्वरकों के परिवहन को पूर्ण सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

यह प्रधान मंत्री द्वारा 23.07.1996 तथा 2.8.1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रधान मंत्री द्वारा की गई अन्य घोषणाओं के अतिरिक्त है।

Assistance given to North-Eastern States

2799. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the total amount of assistance given by the Central Government for rebuilding the economy of the North-Eastern States;

(b) the State-wise basis of seeking assistance as per their needs; and

(c) whether Government propose to grant assistance to each State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (c) Allocation of Normal Central assistance to the States have been made according to Gadgil—Mukherjee formula approved by the National Development Council in December, 1991. Under the formula, 30% of the total divisible pool of Normal Central assistance is set apart in order to meet the requirements of Special Category States (including North Eastern States) Allocations of Normal Central assistance among Special Category States are made keeping in view the available Normal Central assistance, resources of States and their rquirements.

Further, for 1996-97, 30% of the total additional Central assistance provided for Basic Minimum Services to the States was allocated among Special Category States in proportion to the allocation of Normal central assistance for previous year and for slum development on the basis of slum population for 1991. The State-wise allocations of Normal Central assistance made to the North Eastern States for current year are given in the statement attached, *(See* below) while allocations for next year (1997-98) are yet to be finalised.

Statement

Central Assistance to North Eastern States—1996-97

(Rs. Crore)

States	Net Normal Central Assistance*	Basic Minimum Services	Slum Development	Total
1	2	3	4	5
Arunachal Pradesh	383.17	62.18	0.11	445.46
Assam	946.36	154.14	2.22	1102.72
Manipur	282.00	44.30	0.45	326.75**
Meghalaya	227.34	37.03	0.40	264.77
Mizoram	226.37	36.87	0.34	263.58
Nagaland	232.49	37.53	0.24	270.26
Tripura	290.22	46.37	0.39	336.98
Total	2587.95	418.42	4.15	3010.52

*After adjustment of Advance Plan Assistance given in the past.
**Including Rs. 10 crores additional Central Assistance as one time allocation.

Per Capita Income in Rajasthan and Orissa

2800. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the per capita income in Rajasthan and Orissa during 1950, 1980, 1990 and 1996-97; and

(b) the details of new schemes formulated by Government to increase per capita income as well as for raising the standard of people in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND